(v) Power Grid has taken over operation and maintenance of three grid Sub-Stations of DVB.

State-wise Demand and Supply of Power

1600. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the State-wise demand and supply of power in the country during the 8th plan period; and

(b) Government's assistance to the States, State-wise?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM) (a) State-wise power supply position during the various years of 8th Plan is given in Annexure-I. [*See* Appendix 184, Annexure No. 52.]

(b) State-wise entitlement vis-a-vis actual drawal from Central Sector Stations during the 8th Plan period is given in Annexure-II [*See* Appendix 184, Annexure No. 52.]

बांका में एक ग्रिड स्टेशन बनाया जाना

1601. **श्री जनार्दन यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांका (बिहार) में एक ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति 1985 में दी गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि बांका ग्रिड स्टेशन का आधे से अधिक कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (घ) बांका (बिहार) में 2×20 एमवीए 132/33 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु एक परियोजना को बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 1985 में 42.53 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया था। इस परियोजना की संशोधित लागत 600 लाख रुपये है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, लगभग 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस उपकेन्द्र को अक्तूबर, 1999 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विद्युत क्षेत्र का विकास

1602. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत के विकास हेतु बाहरी देशों एवं विदेशी संस्थाओं से कोई सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक योजना-वार कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनों के योजना-वार ब्यौरे और बाह्य सहायता का संचयी समुपयोजन दर्शाने वाला विवरण अनुपत्र में संलग्न है जो कि परियोजना द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का स्पष्ट सूचक है। [देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० —53]

विद्युत वित्त निगम का कार्य-निष्पादन

1603. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन गंभीरतापूर्वक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि मूल्यांकन किया गया है, तो उक्त मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम):

(क) से (ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। निगम वर्ष 1993-94 से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता रहा है और इसका मूल्यांकन प्रति वर्ष सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। पीएफसी समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अच्छा कार्य निष्पादन कर रही है और वर्ष 1993-94 के बाद से उत्कृष्ट दर्जा हासिल करती रही है। निगम के

कार्य निष्पादन की भी सरकार द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

Restructuring of SEBs

1604. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Union Government have any proposal to restructure State Electricity Boards with World Bank's assistance;

(b) if so, the details in this regard and the amount to be made available to SEBs, State-wise;

(c) whether SEBs in their turn have also sent proposals to World Bank for new loans;

(d) to what extent the performance of SEBs would be affected favourably as a result thereof;

(e) whether the loans already taken by SEBs have been properly utilized; and

(f) to what extent Union Government are responsible for repayment of loans by SEBs?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) Some States are restructuring and reforming their power sector with financial and technical assistance from Power Finance Corporation, World Bank, Asian Development Bank. Department for International Development, UK, Canadian International Development Agency and other similar institutions.

(d) Restructuring and reform is expected to improve the operational and financial performance of the power utilities, achieve tariff rationalisation, enhance consumer interest and investor confidence in the power sector.

(e) The utilisation of loans and technical assistance by SEBS/State Governments has largely been in accordance with the agreed schedule of implementation.

(f) Wherever loans have been obtained from multi-lateral agencies by the Government of India, as Borrower, the repayment obligation is that of the Government of India.

Radioactive Impact of Coal

1605. SHRI SANJAY DALMIA:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the quantity of coal actually supplied by the Standing Linkage of radio activity that have occurred in the last three years alongwith the details of action taken thereon till date; and

(b) whether any study was conducted or proposed to be conducted to ascertain the effects of radio activity on the families living nearby these stations?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMRAMANGALAM): (a) and (b) No State Electricity Board has reported radio activity in coal allocated by the Standing Linkage Committee.

विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता

1606. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में ताप तथा जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में मार्च, 1998 के अन्त तक कितनी-कितनी बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी थी;

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में वर्ष-वार कितने-कितने प्रतिशत स्थापित उत्पादन क्षमता का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया गया; और

(घ) क्या देश में उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की सम्भावनाएं हैं; यदि हां, तो जल और ताप क्षेत्र में क्या-क्या सम्भावनायें हैं?